बहुपक्षीय दुनिया के बाद भारत की भूमिका: रणनीतिक स्वायत्तता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग

UPSC प्रासंगिकता:

"प्रारंभिक परीक्षा": बहुपक्षीयता BRICS: ब्रिक्स G-77: जी-77 ASEAN एवं अन्य सामान्य अध्ययन- 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बहुपक्षीयता का ह्रास और द्विपक्षीयता का उभार

समाचार में क्यों है?

बहुपक्षीयता का क्षय और लेन-देन आधारित द्विपक्षीयता का उभार, विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका द्वारा, वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। हाल ही में, 2025 में आयोजित BRICS Summit इस बदलाव का मुकाबला करने में असफल रहा, जिससे वैश्विक दक्षिण की बातचीत की ताकत में स्पष्ट कमी देखने को मिली।

पृष्ठभूमि: बहुपक्षीयता क्या है?

बहुपक्षीयता का मतलब है कि कई देश एक निर्धारित मुद्दे पर सहयोग करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, WTO, या अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति, सहयोग और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए उभरी थी, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण को संगठित वार्ता मंचों जैसे G-77 के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए।

हालांकि, अमेरिका के वैश्विक संधियों से बाहर निकलने (जैसे 2017 में पेरिस समझौता) और संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने के कारण, वैश्विक शासन की संरचना अब खतरे में है।

अमेरिका का बदलाव: बहुपक्षीयता के वास्तुकार से इसके विघटनकर्ता तक

- **संयुक्त राष्ट्र का सीमित प्रभाव:** अमेरिका बढ़ते हुए बहुपक्षीय मंचों को नजरअंदाज करता है (जैसे UNESCO से बाहर निकलना) और लेन-देन आधारित द्विपक्षीयता को प्राथमिकता देता है।
- **टैरिफ और प्रतिबंधों का उपयोग:** उदाहरण के लिए, ईरान और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और चीन के साथ व्यापार युद्ध को भू-राजनीतिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

● **चीन का संकोचन:** अमेरिकी आत्मनिर्भरता अब चीन की वैश्विक प्रभुत्व को सीमित करने पर केंद्रित है, जैसे TikTok पर प्रतिबंध और चिप निर्यात पर प्रतिबंध।

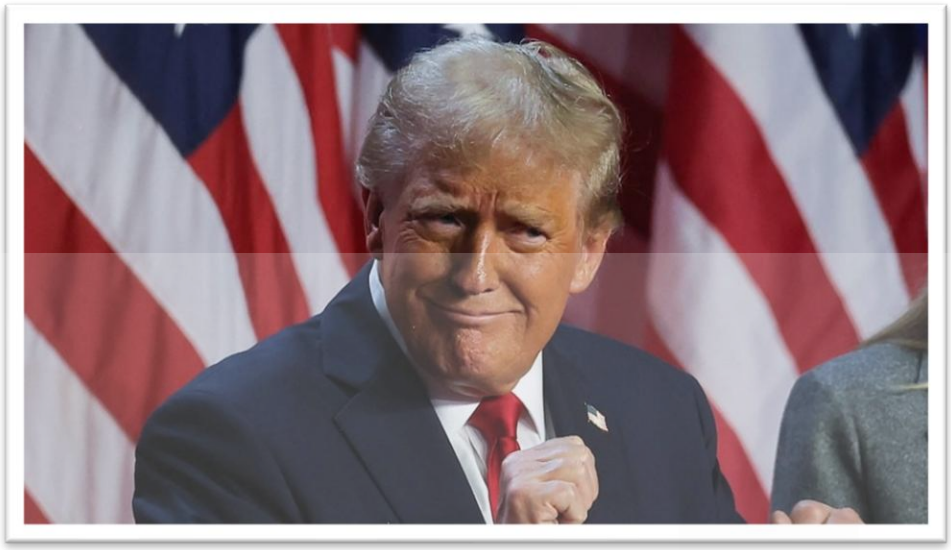

भारत के लिए प्रभाव

1. वैश्विक दक्षिण की सामूहिक बातचीत की गिरावट

• भारत अब केवल बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक प्रभाव के लिए निर्भर नहीं रह सकता।

• उदाहरण: भारत 2025 में UNESCO उपाध्यक्ष पद पर पाकिस्तान से हार गया, जबकि वह इस संगठन का संस्थापक सदस्य था।

2. दक्षिण-दक्षिण आर्थिक पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता

• भारत को प्रतीकात्मक गठबंधनों से विकासशील देशों के बीच ठोस सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए।

• "वैश्विक दक्षिण को जोड़ने वाली शक्ति अब केवल एक मतदान समूह के वित्तीय लाभ नहीं हो सकती।"

• उदाहरण: भारत-आफ्रीका मंच सम्मेलन और भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच (IBSA) को मजबूत किया जाना चाहिए।

3. रणनीतिक स्वायत्तता पर पुनर्विचार

• भारत की विदेश नीति को "रणनीतिक स्वायत्तता" को केवल गैर-राष्ट्रवाद के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य हितों के स्पष्टता के साथ तटस्थता के रूप में अपनाना चाहिए।

• उदाहरण: रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख, जहां उसने रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखा जबकि पश्चिम के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे।

संरचनात्मक प्रतिक्रियाएँ आवश्यक

1. बुनियादी ढांचा-आधारित आर्थिक लचीलापन

भारत को चीन के बुनियादी ढांचे में निवेश के पैमाने की नकल करनी चाहिए:

- उच्च गति रेल, एक्सप्रेसवे, डिजिटल हाईवे
- ऊर्जा-सुरक्षित डेटा सेंटर
- आधुनिक विज्ञान विश्वविद्यालय

उदाहरण: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और गति शक्ति योजना इस दिशा में अग्रसर हैं।

2. नवाचार और तकनीकी नेतृत्व

भारत का GenAI पेटेंट में वृद्धि चौथी औद्योगिक क्रांति में आशा दिखाती है:

- घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना (जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन)
- जनसंख्या लाभ का लाभ उठाकर नवाचार में नेतृत्व करना

3. रक्षा और सुरक्षा सिद्धांत में सुधार

- आधुनिक सैन्य सिद्धांत अब उपग्रहों, साइबर, ड्रोन और एआई द्वारा संचालित हैं।
- उदाहरण: स्वदेशी रक्षा पहलों जैसे DRDO के एआई-आधारित निगरानी ड्रोन, और अग्नि मिसाइल प्रणालियाँ।

सीमा कूटनीति: अतीत के संघर्षों के बजाय विकास को प्राथमिकता देना

- भारत का इंडो-चीन सीमा तनाव और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता (IWT) मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास एक व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है।
- "समझदारी इस बात में है कि कब रुकना है।"
- उदाहरण: भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठकें और पाकिस्तान की IWT को फिर से परखने में रुचि विश्वास निर्माण के उपाय के रूप में।

भारत का BRICS 2026 में अवसर

भारत 2026 में BRICS समिट की मेज़बानी करेगा, जो एक अवसर प्रदान करता है:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को पुनः सक्रिय करना
- सहभागिता से समृद्धि की ओर बदलाव
- वैश्विक दक्षिण के भीतर मूल्य श्रृंखलाओं का पुनर्गठन

"भविष्य समृद्धि को साझा करने में है, न कि सहायता के लिए मोलभाव करने में।"

उदाहरण: भारत द्वारा BRICS विकास बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए प्रस्ताव, जो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देगा।

आगे की चुनौतियाँ

चुनौती	संक्षिप्त विवरण
बहुपक्षीय संस्थानों का कमजोर होना	जैसे WTO, UN जैसे सामूहिक मंचों का प्रभाव घटना
विकसित देशों पर व्यापार निर्भरता	यूएस/ईयू पर अत्यधिक निर्भरता भारत की नीतियों को सीमित करती है
तकनीकी अंतराल	घरेलू नवाचार को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता
सीमा विवाद	आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं से ध्यान भटकाना
सीमित दक्षिण-दक्षिण आर्थिक एकीकरण	वैश्विक दक्षिण देशों के बीच व्यापार और वित्त अभी भी अपर्याप्त है

Result Mitra

उठाए जाने वाले कदम

1. रणनीतिक स्वायत्तता को फिर से परिभाषित करें: राष्ट्रीय हितों के साथ तटस्थता।
2. दक्षिण-दक्षिण व्यापार को बढ़ावा दें: क्षेत्रीय आर्थिक गलियारे स्थापित करें।
3. बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएं: चीन के 2013 मॉडल की तरह बड़े सार्वजनिक निवेश की दिशा में कदम बढ़ाएं।
4. वैश्विक कूटनीति उपकरणों को पुनः संशोधित करें: प्रौद्योगिकी, विकास, और जलवायु नेतृत्व के माध्यम से प्रभाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करें।
5. दक्षिण-दक्षिण संवाद मंचों को संस्थागत रूप से स्थापित करें: BRICS से परे – अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ नए गठबंधनों का निर्माण करें।

निष्कर्ष

जैसा कि हम जानते थे, बहुपक्षीयता अब खत्म होती जा रही है। भारत के लिए आगे का रास्ता अतीत की यादों में नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक, आर्थिक, और तकनीकी रणनीतियों को फिर से संतुलित करने में है — और इसका मुख्य ध्यान आंतरिक ताकत और वैश्विक दक्षिण के भीतर रणनीतिक साझेदारियों पर होना चाहिए। 2026 में BRICS समिट इस महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बन सकता है।

"भारत को वैश्विक व्यवस्थाओं में स्थान की तलाश बंद कर देनी चाहिए और अब उन्हें आकार देना चाहिए।"

प्रैक्टिस प्रश्न:

"भारत किस प्रकार अपनी बहुपक्षीय भागीदारी और विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की प्राप्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है?" (250 शब्द, 15 अंक)